

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 26 / 2026

दायर दिनांक: 23.01.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. कालू पि. ओंकार जाति कुम्हार नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
2. कैलाशचन्द पि. मांग्या जाति कुम्हार नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
3. पीरूलाल पि. मांग्या जाति कुम्हार नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
4. रोडूलाल पि. मांग्या जाति कुम्हार नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
5. श्यामलाल पि. मांग्या जाति कुम्हार नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-

प्रार्थी :- पैरोकार सरकार

अप्रार्थीगण :- एकतरफा



आदेश

दिनांक : 13/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 1062/846 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 1062/846 रकबा 0.0126 हेक्टर किस्म गै.मु. चाह दर्ज है। यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये कुएं का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश



उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

1



दिनांक 30.01.2013 द्वारा किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश की प्रति संलग्न है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाहे नियमन नामान्तरण संख्या 755 दिनांक 02.04.2013 से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। बिन्दु संख्या 3 में वर्णित नियमों के प्रावधानों में गैर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुएं के नियमन के पश्चात मात्र लीज रेंट जमा कराने की शर्त पर लीजधारक दर्ज किया जाना था। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेंट जमा कराया गया है, न ही लीज रेंट की आंक कायनी की गई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 06.03.2026 से उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का डोला की रिपोर्ट, ग्राम गरदनखेडी की सं. 2076 व सं. 2081 की खसरा गिरदावरी, ग्राम गरदनखेडी का नामा.सं. 755 दिनांक 02.04.2013, जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 310, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा का आदेश दिनांक 30.01.2013 की छायाप्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गरदनखेडी के खाता सं. 310 के ख.नं. 1062/846 रकबा 0.0126 गे.मु.चाहे अप्रार्थीगण कालू व मांग्या पिस. ओकार जाति कुम्हार सा.देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला असासुइ (राज०)

सिंचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कृयें खादने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिंचायक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितकरण कर प्रति वर्ष 24/- की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 30.01.2013 से रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पास अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. अभिभाषक पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1062/846 रकबा 0.0126 है. किस्म गे.मु.चाह अप्रार्थीगण कालू व मांग्या पिस. ओंकार जाति कुम्हार सा.देह की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम गरदनखेडी के नामा.सं. 755 दिनांक 02.04.2013 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 15 में **“आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश क्रमांक 10637/राज/13 दिनांक 30.01.2013 की पालना में ख.नं. 846 रकबा 0-01 बीघा भूमि मांग्या, कालू पिस. ओंकार को गे.मु.चाह गैर खातेदारी में दर्ज हेतु नामा. दर्ज कर पेश है”** का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 846 किस्म चरागाह में से 0-01 बीघा भूमि पर बने कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के नियमन/आवंटन आदेश



✓
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला जयपुर (राज०)

5

दिनांक 30.01.2013 के अवलोकन से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सिवायचक भूमि ख.नं. 846 रकबा 0-01 बीघा पर अप्रार्थीगण कालू व मांग्या पिस. ओकार जाति कुम्हार सा.देह द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिकमित कुएं को 24/- प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गैरखातेदार दर्जा करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थीगण द्वारा राशि 5705/- जरिये पी 33 क्रमांक 0030841 से जमा करवाई गई जिसमें 25/- पट्टा शुल्क, 5440/- डीएलसी दर से भूमि की राशि एवं 24/- प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष की लीज रेन्ट 240/- शामिल थे।

7. राजस्थान भूराजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तों पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से - जो भी पहले हो- के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तों के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षों के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षों की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्तें निम्नानुसार हैं -



Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under

✓
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला राजस्थान (राज०)

6

sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.



8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे

W
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झरखण्ड (सफ़ा)

आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में परोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरुद्ध टाईपिंग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 30.01.2013 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिकमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरुस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा लिपीकीय/टाईपिंग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरुस्त किये जाने के प्रावधान है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 1062/846 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।



—:क्रियात्मक आदेश:—

11. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरुस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 1062/846 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरुस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7

W
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला जयवाड़ (राज०)

8

व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13/3/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Y
13/3/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)